

संख्या-16/XIV-1/2017-5(10)/2009

प्रेषक,

बी०एस०मि०

अपर सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निबन्धक,

सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड।

सहकारिता, गन्ना एवं धीनी अनुभाग-1

देहरादून

दिनांक 12 जनवरी, 2017

विषय- वालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहकारी सहभागिता योजना (टी०एस०पी०) के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋणों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्र संख्या-4829/नियो०/सहभागिता/टी०एस०पी०/2016-17 दिनांक 10 अक्टूबर, 2016 एवं पत्र संख्या-6777/नियो०/सहभागिता/टी०एस०पी०/2016-17 दिनांक 03 जनवरी, 2017 तथा वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत करने विषयक विल विभाग के पत्र संख्या-490/XXVII (1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं विल अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई, 2016 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सहकारी सहभागिता योजना (टी०एस०पी०) के अन्तर्गत दिये जाने वाले कृषि/कृषयेतर ऋणों के अधीन लघु एवं सीमान्त कृषकों, बी०पी०एल०परिवारों के कृषकों को अल्पकालीन/मध्यकालीन/दीर्घकालीन ऋणों पर लागू व्याज दरों के सापेक्ष राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वहन किए जाने वाले व्याज अनुदान की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि ₹० 80,00,000/- (रुपये अस्सी लाख मात्र) के व्यय हेतु अवमुक्त करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) योजनान्तर्गत राज्य सरकार के अश हेतु सहकारी संस्थाओं से प्राप्त दावों का निबन्धक स्तर से सम्यक परीक्षण एवं त्रैमासिक प्रगति समीक्षा उपरान्त ही सहकारी संस्थाओं को वित्तीय स्वीकृति की धनराशि प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी एवं अग्रिम भुगतान अनुमत्य नहीं होगा। चालू वर्ष में स्वीकृत ऋणों पर लागू व्याज दरों के सापेक्ष दिनांक 31 मार्च, 2017 तक ही सस्ते ऋण के सापेक्ष

(2)

(4) धनसंश्लेष का उपयोग केवल उन्हीं मदों पर किया जाए, जिसके लिये स्वीकृति दी जा रही है। यदि इसका उपयोग अन्यथा किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे तथा उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए अप्राधिकृत व्यय की वसूली की जायेगी।

(5) धनसंश्लेष का योजनावार व्यय विवरण निबन्धक प्रत्येक माह बी0एम0-13 प्रारूप पर नियमित रूप से वित्त विभाग/शासन तथा महालेखाकार कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2425-सहकारिता-आयोजनागत-00-796-जनजाति क्षेत्र उप योजना-05-सहकारी सहभागिता योजना-00-20-सहायक अनुदान/अश्वदान/राज सहायता के नामे जाला जायेगा।

3. उपर्युक्त आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-490/XXVII (1)/2016 दिनांक 31 मार्च 2016 एवं पत्र संख्या-847/XXVII(1)/2016 दिनांक 26 जुलाई 2016 द्वारा दिये गये विस्तृत दिशा निर्देशों के कम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्नक-आई0डी0 मूल में।

भवदीय,

(बी0एम0सिअ)

अपर सचिव।

संख्या-16(1)/XIV-1/2017, तदुद्दिनांकित।

1 महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी ओवरसैय बिल्डिंग, माजरा, उत्तराखण्ड, देहरादून।

2 वित्त-4/नियोजन/भाषा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।

3 आयुक्त, कुमायू/गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।

4 मुख्य महाप्रबन्धक, नार्बार्ड क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

5 समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

6 वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, अल्मोड़ा।

7 समस्त जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तराखण्ड द्वारा निबन्धक।

8 प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी बैंक लि0, देहरादून।